धीरेंद्र कुमार मंडल

बनाम

पश्चिम बंगाल सरकार और एक अन्य

जरिये कानूनी सहयोगियों के पर्यवेक्षक और सलाहकार

(मेहर चंद महाजन सी.जे., मुखर्जी, विवियन

बोस भगवती और अय्यर जेजे.)

भारत का संविधान, अनुच्छेद 14-उचित वर्गीकरण के अर्थ का दायरा और निर्माण-आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम 5), उप धारा 269 (1), 536,धारा 269 (1) के तहत अधिसूचना-कुछ व्यक्तियों के लिए जूरी द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधिकार की वैधता-समान या समान अपराध करने वाले अन्य व्यक्तियों के मामले में बनाए गए अधिकार-मुकदमे में दोष-अगर इसे धारा 536 द्वारा ठीक किया गया।

जूरी द्वारा मुकदमा निस्संदेह सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक है जो एक अभियुक्त के पास हो सकता है, लेकिन इसकी संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) एक सक्षम करने वाली धारा है और राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष सभी अपराधों या अपराधों के किसी विशेष वर्ग का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाए। इसके पास इस तरह के आदेश को रद्द करने या

बदलने की और शक्ति है। यदि राज्य सभी या किसी विशेष वर्ग के अपराधों के संबंध में किसी भी जिले में जूरी द्वारा मुकदमा बंद कर देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह धारा राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं देती है कि किसी विशेष मामले या किसी विशेष आरोपी व्यक्ति का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाए, जबकि उसी अपराध के आरोपी अन्य व्यक्तियों का मुकदमा जूरी द्वारा नहीं किया जाएगा। इस धारा में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि एक ही अपराध के आरोपी लेकिन अलग-अलग मामलों में शामिल व्यक्तियों पर सत्र न्यायालय द्वारा एक अलग प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात् उनमें से कुछ जूरी द्वारा और उनमें से कुछ मूल्यांकनकर्ताओं की मदद से। प्रतिसंहरण या परिवर्तन की शक्ति का दायरा खंड के प्रारंभिक शब्दों द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ सह-व्यापक है और उन शब्दों से परे नहीं जा सकता है।

पिछली दो अधिसूचनाओं को निरस्त करने वाली वर्ष 1947 की आक्षेपित अधिसूचना ने कुछ व्यक्तियों को जूरी द्वारा मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित कर दिया था, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामले में उस अधिकार को बनाए रखा था जिन्होंने समान या इसी तरह के अपराध किए थे और इस प्रकार यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (I) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों से परे चला गया था और इस प्रकार शून्य और निष्क्रिय था।

आक्षेपित अधिसूचना ने संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया क्योंकि वर्गीकरण कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित नहीं था जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ न्यायसंगत और उचित संबंध रखता था, लेकिन इसे मनमाना और बिना किसी ठोस आधार के बनाया गया था।

आक्षेपित अधिसूचना स्पष्ट शब्दों में उन आधारों का संकेत नहीं देती है जिनके आधार पर मामलों के इस समूह को भारतीय दंड संहिता की समान धाराओं के तहत आने वाले मामलों के अन्य समूहों से अलग किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए वर्गीकरण का इन मामलों में जूरी परीक्षण को वापस लेने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था।

यह तर्क कि परीक्षण में दोष, यदि कोई हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 536 द्वारा ठीक किया गया था क्योंकि यह आपत्ति विचारण न्यायालय में नहीं ली गई थी, बलहीन था क्योंकि धारा 536 कार्यवाही शुरू होने के बाद मुकदमे में अनियमितताओं को अभिनिर्धारित करती है, लेकिन यह धारा 269 (1) के तहत की गई अधिसूचना से संबंधित नहीं है जो उस धारा की सीमाओं से परे है या जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

यह आपत्ति जो न्यायालय की अधिकारिता की जड़ तक जाती है, किसी भी स्तर पर ध्यान में रखी जा सकती है।

1947 में जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना उस अध्यादेश की तर्ज पर थी जो अनवर अली सरकार के मामले [1952] एस.सी.आर. 284) में विचाराधीन था।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार ([1952] एस.सी.आर. 284), रानी-महारानी बनाम गणपति वरमियानार और अन्य (आई.एल.आर. 23 मद्रास 637), सैयद करीम रजवी बनाम हैदराबाद राज्य ([1953] एस.सी.आर. 589), हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य ([1953] एस.सी.आर. 661), लछमनदास केवल राम आहूजा बनाम बॉम्बे राज्य ([1952] एस.सी.आर. 710), काठी रानींग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य ([1952] एस.सी.आर. 435), केदार नाथ बाजोरिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ([1954] एस.सी.आर. 30) संदर्भित किया गया है।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार 1952 की आपराधिक अपील सं. 48।

संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (सी) के तहत दिनांक 21 मार्च, 1952 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न अपील। भारत का संविधान।, कलकत्ता उच्च न्यायालय (दास गुप्ता और लाहिड़ी जेजे.) की आपराधिक अपील संख्या 1950 की 77 में, जो 29 अप्रैल, 1950 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बर्दवानिन सत्र परीक्षण संख्या 1950 के न्यायालय के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धवान के न्यायालय के 29 अप्रैल, 1950 के सत्र विचारण संख्या 1 के निर्णय और आदेश से उद्भूत 1950 की आपराधिक अपील

संख्या 77 में कलकत्ता उच्च न्यायालय (दास गुप्ता और लाहिरी जेजे.) के 21 मार्च, 1952 के निर्णय और आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (सी) के तहत अपील।

अपीलार्थी की ओर से एन.सी. चक्रवर्ती और सुकुमार घोष।

प्रतिवादी के लिए बी. सेन और आई.एन. श्रॉफ।

मध्यस्थ (भारत संघ) के लिए जी.एन. जोशी और पी.जी. गोखले। 20 अप्रैल, 1954 न्यायालय का निर्णय मेहर चंद महाजन सी. जे. द्वारा दिया गया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (सी) के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय के 21 मार्च, 1952 के फैसले के खिलाफ एक अपील है, जिसमें उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन वर्धवान के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे दी गई सजा को कम कर दिया। अपील एक श्रृंखला से संबंधित हैः ऐसे मामले जिन्हें आम तौर पर "द वर्धवान टेस्ट रिलीफ फ्रॉड केस" के रूप में जाना जाता है, जिनकी उत्पत्ति उस वर्ष बंगाल के अकाल के दौरान 1943 में वर्धवान जिले में आयोजित परीक्षण राहत अभियानों में हुई थी। जिले में अकाल पीड़ित लोगों की तीव्र कमी और मौजूदा संकट के कारण तत्काल राहत और परीक्षण राहत कार्य जिला मजिस्ट्रेट की सलाह के अनुसार जिला बोर्ड द्वारा शुरू किए गए थे। बंगाल सरकार ने इस तरह के परीक्षण राहत कार्यों के लिए जिला बोर्ड को अग्रिम रूप से चार लाख रुपये की मंजूरी दी। हालाँकि, जिला बोर्ड ने

सीधे राहत कार्य करने के बजाय, कमीशन के आधार पर कई एजेंटों को नियुक्त किया, जिनके माध्यम से परीक्षण राहत कार्य किए गए। यह बंगाल अकाल संहिता और अकाल नियमावली, 1941 का स्पष्ट उल्लंघन था और जैसे-जैसे बहुत बड़ी राशि खर्च की जा रही थी, सरकार को अपने एजेंटों के माध्यम से किए गए परीक्षण राहत कार्य के बारे में संदेह पैदा हुआ। इसके परिणामस्वरूप जांच शुरू हुई और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ कई मामले शुरू किए गए और अपीलार्थी का मामला उनमें से एक है। सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि ये मामले जूरी द्वारा सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं थे और तदनुसार 24 फरवरी, 1947 को मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से सत्र न्यायालय द्वारा इन मामलों की सुनवाई के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना इन शर्तों में हैः- "संख्या 4591-17 फरवरी, 1947-जबकि उसी दिनांक को कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित 27 मार्च, 1893 की एक अधिसूचना द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 1 अप्रैल, 1893 को और उसके बाद, वर्धवान जिले सहित कुछ जिलों में किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपराधों का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाएगा "और जबकि 28 सितंबर, 1939 के कलकत्ता राजपत्र के भाग। के पृष्ठ 2505 पर प्रकाशित 22 सितंबर, 1939 की अधिसूचना संख्या 33471 द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 1 जनवरी, 1940 को और उससे भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अन्य अपराधों का मुकदमा किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष जूरी द्वारा किया जाएगा" और जबकि कुछ व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा

120-बी, 420, 467, 468, 471 और 477-ए के तहत अपराध करने का आरोप है, जिन्हें 'वर्धवान परीक्षण राहत धोखाधड़ी मामलों' के रूप में जाना जाता है, जिनमें से दो मामलों में आरोपी व्यक्ति, अर्थात् सम्राट बनाम धीरेंद्र नाथ चटर्जी और अन्य और (2) सम्राट बनाम गुलाम रहमान और अन्य, मुकदमे के लिए वर्धवान में सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध हैं और शेष मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों को इसके बाद मुकदमे के लिए उक्त न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध किया जा सकता है। "अब, इसलिए, राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 269 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचनाएँ जहाँ तक वे मुकदमे पर लागू होती हैं, उन अपराधों के बारे में जिनके साथ उक्त मामलों में अभियुक्तों पर सत्र न्यायालय में आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें रद्द करने के लिए सहमत हैं। इस अधिसूचना के अनुसरण में अपीलार्थी को छह अन्य लोगों के साथ वर्धवान के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे के लिए भेजा गया था। उनके खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 20-बी के साथ धारा 420 के तहत वर्धवान जिले के परीक्षण राहत कार्यों के बोर्ड प्रभारी और इसके कुछ अधिकारी को धोखा देने की साजिश के लिए लगाया गया था। 21 मई और 21 जुलाई, 1943 के बीच अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत जालसाजी के 24 मामलों में भी आरोप लगाया गया था। संहिता और इन मामलों में अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उसने वेतन पत्रों पर अपने अंगूठे के निशान लगाकर जालसाजी की, जिस पर वर्धवान में लोगों की राहत के लिए एक योजना के

हिस्से के रूप में बनाई गई सड़क पर किए गए काम के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अंगूठे के निशान लिए जाने चाहिए थे। वह एक एजेंट, ज्ञानेंद्र नाथ चौधरी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से एक थे, और यह उनका कर्तव्य था कि वे गिरोह के प्रभारी साथियों को पैसे वितरित करें और भुगतान की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में वेतन पत्रों पर अंगूठे का निशान लें। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने आरोपों में उल्लिखित कई मामलों में पूर्ण जानकारी के साथ अपने अंगूठे के निशान लगाए कि कोई भुगतान नहीं किया गया था और अंगूठे के निशान के खिलाफ काल्पनिक व्यक्तियों के नाम लगाए ताकि यह प्रतीत हो सके कि भुगतान वास्तविक व्यक्तियों को किया गया थाः और इस प्रक्रिया से अपने और अपने नियोक्ताओं के लिए गलत लाभ प्राप्त किया था। बचाव में अपीलार्थी का निवेदन था कि अंगूठे के निशान उसके नहीं थे और वैकल्पिक रूप से अगर अंगूठे के निशान उसके थे, तो वह उन्हें उन व्यक्तियों के अधिकार में रखता था जिनके नाम अंगूठे के छापों के खिलाफ दिखाए गए थे और इन अंगूठे के छापों को डालने में वह बेईमानी या धोखाधड़ी से काम नहीं करता था।अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया और इसे स्वीकार कर लिया गया। अनुमति के समय यह तर्क दिया गया था कि रद्द करने की सूचना द्वारा राज्य सरकार जूरी द्वारा विशेष व्यक्तियों को मुकदमे के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है और उसी वर्ग या अपराधों के वर्गों के आरोपित अन्य व्यक्तियों को

जूरी द्वारा मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं दे सकती है। पीठ ने सोचा कि यह काफी कठिन विषय था और इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना उचित था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारे सामने दो बिंदुओं पर जोर दिया। पहले उदाहरण में, उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों से अधिक थी और यह उस धारा से परे चली गई थी। दूसरा यह आग्रह किया गया कि अधिसूचना अपीलार्थी को कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करती है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उसके मौलिक अधिकार का संक्षिप्त रूप है और उच्च न्यायालय का यह विचार कि वर्गीकरण मनमाना या टालमटोल वाला नहीं था, गलत था। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र सरकार को अपने अनुरोध पर इस अपील में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए इस तर्क को देखते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) संविधान के भाग III के प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण अमान्य थी। हालाँकि, हस्तक्षेप अनावश्यक हो गया क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने सुनवाई में इस बिंदु को छोड़ दिया और हमारे सामने इस पर बहस नहीं की। जहाँ तक विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए दो बिंदुओं का संबंध है, हमें ऐसा लगता है कि उठाए गए दोनों तर्क अच्छी तरह से स्थापित हैं। हमारी राय में अधिसूचना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) के दायरे से परे है। यह खंड इस प्रकार है:-

"राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में आदेश देकर निर्देश दे सकती है कि किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष सभी अपराधों या किसी विशेष वर्ग के अपराधों का मुकदमा किसी भी जिले में जूरी द्वारा किया जाएगा और ऐसे आदेश को निरस्त या परिवर्तित कर सकती है। हालाँकि जूरी द्वारा मुकदमा निस्संदेह सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक है जो अभियुक्त के पास हो सकता है, लेकिन इसकी संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) एक सक्षम करने वाली धारा है और राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष सभी अपराधों या अपराधों के किसी विशेष वर्ग का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाएगा। इसके पास इस तरह के आदेश को रद्द करने या बदलने की और शक्ति है। यदि राज्य सभी या किसी विशेष वर्ग के अपराधों के संबंध में किसी भी जिले में जूरी द्वारा मुकदमा बंद कर देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामले या किसी विशेष आरोपी का मुकदमा जूरी द्वारा सत्र न्यायालय में होगा, जबकि उसी अपराध से जुड़े अन्य मामलों के संबंध में मुकदमा मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से होगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारा राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं देती है कि किसी विशेष मामले या किसी विशेष अभियुक्त व्यक्ति का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाएगा, जबकि उसी अपराध के आरोपी अन्य व्यक्तियों का मुकदमा जूरी द्वारा नहीं किया जाएगा। धारा में प्रयुक्त भाषा के स्पष्ट निर्माण पर यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को यह निर्देश

देने का अधिकार दिया गया है कि किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष सभी अपराधों या अपराधों के किसी विशेष वर्ग का मुकदमा किसी भी जिले में जूरी द्वारा किया जाएगा। यह धारा व्यक्तिगत अभियुक्त या व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान नहीं देती है। यह केवल अपराधों या अपराधों के एक विशेष वर्ग की बात करता है, और विशेष मामलों या मामलों के वर्गों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है और यह परिकल्पना नहीं करता है कि एक ही अपराध के आरोपी लेकिन विभिन्न मामलों में शामिल व्यक्तियों पर सत्र न्यायालय द्वारा एक अलग प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात्, उनमें से कुछ जूरी द्वारा और उनमें से कुछ मूल्यांकनकर्ताओं की मदद से। प्रतिसंहरण या परिवर्तन की शक्ति का दायरा खंड के प्रारंभिक शब्दों द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ सह-व्यापक है और उन शब्दों से परे नहीं जा सकता है। प्रतिसंहरण की शक्ति का प्रयोग करते हुए भी राज्य सरकार किसी विशेष मामले या मामलों के समूह को नहीं चुन सकती है और अधिसूचना को केवल इन मामलों के लिए रद्द नहीं कर सकती है और उसी अपराध के लिए आरोपित अन्य व्यक्तियों के मामलों को जूरी द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं छोड़ सकती है. उसी अपराध के लिए आरोपित अन्य व्यक्तियों के मामलों को जूरी द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य नहीं छोड़ सकती है। यह न्यायमूर्ति श्री चक्रवर्ती द्वारा इस खंड के संबंध उनकी धारणा थी और हम में से कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार [1952] एस.सी.आर 284-326 में इस न्यायालय में इसका समर्थन किया था। यह इंगित किया गया था कि किसी विशेष मामले या

किसी विशेष आरोपी के संबंध में जूरी परीक्षण को रद्द नहीं किया जा सकता है, जबकि उन्हीं अपराधों से जुड़े अन्य मामलों के संबंध में आदेश अभी भी लागू है।

इस मामले में अधिसूचना स्पष्ट रूप से वर्धवान परीक्षण राहत धोखाधड़ी मामलों में आरोपित व्यक्तियों को संदर्भित करती है और धारा 120-बी, 467, 468, 477 आदि के तहत जूरी अपराधों द्वारा विचारण योग्य अपराधों की श्रेणी से नहीं हटाती है, चाहे किसी विशेष क्षेत्र के भीतर किसके द्वारा किया गया हो या किया गया हो। अभियुक्त के अलावा और धारा 120-बी, 420, 467, 468, 477 के तहत अपराधों में शामिल व्यक्तियों के मामले अभी भी जूरी द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं।

1893 की पूर्व अधिसूचना और 1939 की दूसरी अधिसूचना की भाषा, जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि कुछ जिलों में कुछ अपराधों का सत्र न्यायालय में मुकदमा जूरी द्वारा किया जाएगा, महत्वपूर्ण है और आक्षेपित अधिसूचना के संचालन भाग में उपयोग की जाने वाली भाषा के बिल्कुल विपरीत है। 27 मार्च, 1893 की अधिसूचना द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 1 अप्रैल, 1893 को या उसके बाद, वर्धवान जिले सहित कुछ जिलों में किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपराधों का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाएगा कि इस अधिसूचना में किसी भी व्यक्ति या विशेष अभियुक्त व्यक्तियों के मामलों का कोई संदर्भ नहीं

है, यह अपनी शर्तों में सामान्य है। 22 सितंबर, 1939 की अधिसूचना द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 1 जनवरी, 1940 को और उससे, किसी भी सत्र न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अन्य अपराधों का मुकदमा जूरी द्वारा किया जाएगा। यह अधिसूचना सामान्य शब्दों में भी है। दूसरे शब्दों में, पहली अधिसूचना में अपराधों की एक अनुसूची बनाई गई और निर्देश दिया गया कि उन अपराधों पर, चाहे वे किसी भी तथ्य के आधार पर किए गए हों, जूरी द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए। दूसरी अधिसूचना ने उस सूची में कई अन्य अपराधों को जोड़ा। प्रतिसंहरण आदेश किसी भी अपराध को सूची से नहीं घटाता है; यह उन्हें अक्षुण्ण छोड़ देता है। यह जो करता है वह यह है कि यह कुछ व्यक्तियों को जूरी द्वारा मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामले में उस अधिकार को बनाए रखता है जिन्होंने समान या इसी तरह के अपराध किए हैं और इस संबंध में यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति से परे है और इस प्रकार शून्य और निष्क्रिय है।

हमारा यह भी मानना है कि अधिसूचना भी खराब है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर नकार दिया कि इन मामलों में जूरी परीक्षण को वापस लेने के लिए किया गया वर्गीकरण उचित था और न तो मनमाना था और न ही टालमटोल करने वाला था। यह कहा गया था कि इन मामलों ने मामलों के एक वर्ग का गठन किया और उनकी सामान्य विशेषता यह थी कि

अंगूठे के छापों की वास्तविकता के बारे में और व्यक्तियों के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में सबूतों के एक बड़े समूह पर विचार करने की आवश्यकता थी और यह इतना लंबा समय लेने के लिए बाध्य था कि एक जूरी सदस्य के लिए सबूत का उचित माप रखना बहुत मुश्किल होगा, यह असंभव नहीं है, और ये सामान्य विशेषताएं इस वर्ग के मामलों को भारतीय दंड संहिता की समान धाराओं के तहत अपराधों से जुड़े अन्य मामलों से अलग करती हैं।अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यद्यपि अनुच्छेद 14 किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेदभावपूर्ण विधान के लिए एक विशेष विषय के रूप में अलग किए जाने से रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह निहित नहीं है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो प्रकृति, प्राप्ति या परिस्थिति से एक ही स्थिति में नहीं हैं, और यह कि वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा राज्य को यह निर्धारित करने की शक्ति है कि कानून के उद्देश्यों के लिए और किसी विशेष विषय पर अधिनियमित कानून के संबंध में किसे एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए; लेकिन वर्गीकरण, हालांकि, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ न्यायपूर्ण और उचित संबंध रखने वाले कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए और इसे मनमाने ढंग से और बिना किसी ठोस आधार के नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना में, स्पष्ट शब्दों में, उन आधारों का संकेत नहीं दिया गया है जिनके आधार पर मामलों के इस समूह को भारतीय दंड संहिता की समान धाराओं के तहत आने वाले मामलों के अन्य समूह से अलग किया गया है। हालाँकि, उच्च

न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने सोचा कि मामलों के इस समूह को एक वर्ग में रखा गया था क्योंकि उनकी सामान्य विशेषता यह थी कि अंगूठे के छापों की वास्तविकता के बारे में और व्यक्तियों के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में एक बड़े पैमाने पर साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता थी और इसमें इतना लंबा समय लगना तय था कि एक जूरी सदस्य के लिए साक्ष्य का उचित माप रखना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। हमारी राय में; इस वर्गीकरण का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोई संबंध नहीं है; यानी इन मामलों में जूरी परीक्षण को वापस लेना अन्य मामलों या मामलों के सेट में एक ही अपराध के आरोपी व्यक्तियों के मामले में बहुत सारे सबूत हो सकते हैं। साक्ष्य के एक समूह की मात्र परिस्थिति, और यह सुझाव कि लंबे समय के कारण जूरी सदस्य भूल सकते हैं कि उनके सामने क्या सबूत पेश किया गया था, इन व्यक्तियों को जूरी द्वारा मुकदमे के अधिकार से वंचित करने के लिए कोई उचित आधार प्रदान नहीं करता है। यह देखना मुश्किल है कि उन मामलों के संबंध में मूल्यांकनकर्ताओं से जूरी सदस्यों की तुलना में बेहतर स्मृति की उम्मीद कैसे की जा सकती है जिनमें साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा दर्ज किया जाना है और जिसमें लंबा समय लग सकता है। यह दैनिक अनुभव की बात है कि डकैती, साजिश, हत्या आदि के कई मामलों में जूरी ट्रायल होते हैं। जहाँ मुकदमा महीनों और महीनों तक चलता है और बहुत सारे सबूत होते हैं। केवल इसी आधार पर एक जूरी परीक्षण से इनकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इसे अस्वीकार करने के लिए एक उचित आधार नहीं है। जूरी सदस्यों,

मूल्यांकनकर्ताओं, न्यायाधीशों और अन्य व्यक्तियों की स्मृति, जिन्हें किसी भी मामले के तथ्यों पर अपना निर्णय लेना होता है, वर्गीकरण और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार करने के लिए कोई उचित आधार नहीं दे सकती है। इसी तरह, किसी विशेष मामले में साक्ष्य की मात्रा वर्गीकरण के लिए कोई उचित आधार नहीं बना सकती है और इस प्रकार विचार में वस्तु के साथ कोई न्यायसंगत संबंध नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित विशेषताएँ जालसाजी, साजिश, डकैती आदि के सभी मामलों में समान हो सकती हैं।

प्रत्यर्थी राज्य के लिए श्री सेन ने पहली बार शीर्षक में तर्क दिया कि मुकदमे में दोष, यदि कोई हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 536 के प्रावधानों द्वारा ठीक किया गया था क्योंकि यह आपत्ति निचली अदालत में नहीं ली गई थी। हमारी राय में, यह तर्क बलहीन है कि धारा 536 कार्यवाही शुरू होने के बाद मुकदमे में अनियमितताओं को अभिनिर्धारित करती है, लेकिन यह धारा 269 (1) के तहत की गई अधिसूचना से संबंधित नहीं है जो उस धारा की सीमाओं से परे जाती है या जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। यह तर्क वर्तमान जैसे मामले पर लागू नहीं हो सकता है। अदालत के पास जूरी द्वारा मुकदमे का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं थी जब सरकार ने इन मामलों के संबंध में अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसके अलावा आपत्ति की प्रकृति ऐसी है कि यह न्यायालय की अधिकारिता के मूल तक जाती है और ऐसी आपत्ति पर किसी भी स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है। श्री सेन ने क्वीन-एम्प्रेस बनाम गणपति वन्नियार और अन्य (1) मामले में मद्रास उच्च

न्यायालय के एक पीठ के फैसले पर भरोसा जताया। वहाँ के मामले पर ऊपर उल्लिखित दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया था और हमें नहीं लगता कि उस मामले का सही निर्णय लिया गया था। श्री सेन ने आगे तर्क दिया कि किसी भी मामले में इस मामले में अधिसूचना संविधान के लागू होने से तीन साल पहले फरवरी, 1947 में जारी की गई थी, और हालांकि संविधान के लागू होने से पहले मुकदमा समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन सत्र न्यायालय द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं की मदद से शुरू किया गया मुकदमा एक अच्छा मुकदमा था और यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे किसी भी तरह से दूषित किया गया था। अब यह स्पष्ट है कि यदि यहाँ मूल्यांकनकर्ता जूरी सदस्यों की स्थिति में थे और उन्होंने इस मामले की तरह "दोषी नहीं" का निर्णय दिया, तो अभियुक्त को तब तक बरी कर दिया गया जब तक कि सत्र न्यायाधीश के पास मुकदमे को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ देने का कारण न हो। स्पष्ट रूप से इसलिए अभियुक्त को संविधान के उद्घाटन के बाद जारी मुकदमे और एक ऐसी प्रक्रिया के तहत पूर्वाग्रह था जो संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के साथ असंगत थी। इसे इसलिए भी दूषित किया गया था क्योंकि इसे अधिकृत करने वाली अधिसूचना भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 (1) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों से परे थी।

श्री सेन, इस तर्क के लिए कि 1947 की अधिसूचना के तहत संविधान के उद्घाटन के बाद मुकदमे को जारी रखना, भले ही वह अधिसूचना चरित्र में

भेदभावपूर्ण थी, अमान्य नहीं था, इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा रखता है (1) सैयद कासिम रजवी बनाम हैदराबाद राज्य [1953] एससीआर 589 और (2) हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य [1953] एस.सी.आर. 661। हमारी राय में, ये निर्णय, उनके तर्क में मदद करने के बजाय, इस मामले के तथ्यों के संबंध में पूरी तरह से नकारात्मक हैं। इन दोनों निर्णयों में, यह इंगित किया गया था कि यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या अभियुक्त अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षण से वंचित था, न्यायालय को सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करने के बाद भी अभियुक्त को सामान्य कानून के तहत मुकदमे का पर्याप्त लाभ प्राप्त करना संभव था; और, यदि ऐसा है, तो क्या यह वास्तव में विशेष मामले में किया गया था। अब यह स्पष्ट है कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आयोजित मुकदमे को जूरी द्वारा मुकदमे में बदलना असंभव है और जूरी द्वारा मुकदमे को उस स्तर पर पेश नहीं किया जा सका जहां अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया चरित्र में भेदभावपूर्ण हो गई थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कानून के भेदभावपूर्ण प्रावधान को बाकी से अलग किया जा सकता है, फिर से, इस तरह के मामलों में प्रक्रिया के मामले में अभियुक्त के लिए समानता का एक उचित उपाय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सैयद कासिम रजवी के मामले में बताया गया है यदि सामान्य प्रक्रिया जूरी द्वारा या मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से की जाती है, और वास्तव में शुरुआत में कोई जूरी या मूल्यांकनकर्ता परीक्षण नहीं था, तो इसे किसी भी बाद के चरण में पेश करना

संभव नहीं होगा और एक बार संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाने के बाद बाद की दिनांक में एक अलग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में पूरे मुकदमे की खराब के रूप में निंदा करनी होगी। लछमनदास केवलराम आहूजा बनाम बम्बई राज्य [1952] एस.सी.आर. 710 के मामले में इस न्यायालय का भी यही दृष्टिकोण था, वह मामला इस धारणा पर आगे बढ़ा कि 26 जनवरी, 1950 के बाद विशेष न्यायालय के लिए भेदभावपूर्ण प्रक्रिया से बचना संभव नहीं था। इसलिए मुकदमा खराब था इन टिप्पणियों को देखते हुए, श्री सेन के तर्क के इस हिस्से को स्वीकार करना संभव नहीं है।

श्री सेन ने अपने शांत तरीके से सुझाव दिया कि काठी रानींग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य [1952] एस.सी.आर 435 और केदार नाथ बाजोरिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [1954] एस.सी.आर. 30 में इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, अनवर अली सरकार के मामले (3) में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार एक विशेष मामले को चुनकर मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय में नहीं भेज सकती थी, ने अपना बहुत अधिक बल खो दिया था। हमें ऐसा लगता है कि यह सुझाव एक गलत धारणा पर आधारित है कि अनवर अली सरकार के मामले (3) और सौराष्ट्र मामले (1) या केदार नाथ बाजोरिया (2) के मामले में निर्णय के बीच कोई वास्तविक टकराव है। केदार नाथ बाजोरिया के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि क्या कुछ अपराधों के मुकदमे के लिए विशेष

प्रक्रिया का प्रावधान करने वाला अधिनियम भेदभावपूर्ण है या नहीं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह उत्पन्न होता है, और सभी मामलों पर लागू होने वाला कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अनुच्छेद 14 के लागू होने के प्रश्न पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 के निर्माण या दायरे के बारे में किसी भी सिद्धांत पर कोई अंतर नहीं है। केदार नाथ बाजोरिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2) में बहुमत के फैसले ने अनवर अली सरकार के मामले (3) को इस आधार पर अलग किया कि बाजोरिया के मामले (2) में कानून एक वर्गीकरण पर आधारित था, जो युद्ध के बाद की असामान्य आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में आसानी से समझ में आने योग्य था और स्पष्ट रूप से विधायी उद्देश्य को कम करने के लिए गणना की गई थी, लेकिन उस निर्णय की शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया। वर्तमान अधिसूचना अनवर अली सरकार के मामले (3) में विचाराधीन अध्यादेश की तर्ज पर अधिक है और इसका अध्यादेश और सौराष्ट्र मामले (1) या केदार नाथ बाजोरिया (2) के मामले में विचार की गई उपस्थित परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है और उस निर्णय के आलोक में यह माना जाना चाहिए कि 1947 में जारी की गई अधिसूचना संविधान के लागू होने पर चरित्र में भेदभावपूर्ण हो गई थी और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित हुई थी।

इसलिए परिणाम यह है कि 26 जनवरी, 1950 के बाद सत्र न्यायाधीश द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से अपीलार्थी का मुकदमा खराब था और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, यह न्याय के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाएगा यदि इस स्तर पर इस मामले में जूरी द्वारा एक नए मुकदमे का आदेश दिया जाता है। इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि उसे रिहा किया जाए।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सुनील कुमार की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।